ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) से (ग) स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) की मार्फत वित्तपोषित परियोजनाएं हैं। कपार्ट ने इसके द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए विभिन्न अनुभवी लोगों का निगरानीकर्ताओं के रूप में पैनल बनाया है। सामान्य निगरानी प्रक्रिया के अतिरिक्त जब कभी भी किसी स्वयंसेवी एजेंसी द्वारा परियोजना के अनुचित क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, निगरानीकर्ता के माध्यम से आवश्यक जांच कराई जाती है। जब कभी आवश्यक होता है, कपार्ट मामले की जांच करने के लिए अपने अधिकारियों को तैनात करता है अथवा इसके लिए संबंधित राज्य सरकार से आग्रह करता है।

बिहार में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र

1456. श्री रामदेव भंडारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी जिले में कापार्ट द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को अब तक प्रदान की गई धनराशि में से सामाजिक-शक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही, झंझारपुर को कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) इस क्षेत्र में अनेक संस्थाओं के होते हुए एक विशेष संस्था का ही इतनी बड़ी धनराशि देने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस संस्था के विरूद्ध प्रखण्ड विकास अधिकारी के स्तर पर जांच लम्बित पड़ी है ;

(ङ) क्या उक्त संस्था के सचिव ने जांच कार्यवाही को प्रभावित और विफल करने के लिए लोगों के समूह को लेकर प्रखण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में आपराधिक उत्पात किया था और प्रखण्ड विकास अधिकारी ने उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी ; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त संस्था के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गुजरात की ग्रामीण/आदिवासी महिलाओं को स्व-रोजगार दिया जाना

1457. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भरूच, सूरत बड़ोदरा और पंचमहल जिलों के आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्व-रोजगार दिये जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ग) गुजरात की ग्रामीण/जनजातीय महिलाओं को स्व-रोजगार मुहैया कराने के लिए अलग से कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना तथा समन्वित ग्रामीण

विकास कार्यक्रम जैसी योजनायें भडौच, सूरत, वड़ोदरा तथा पंचमहल सहित गुजरात के सभी जिलों में पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना का प्रारंभिक उद्देश्य स्वपोषित आधार पर आय सृजन गतिविधियों के अवसर सृजित करके गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों की महिला सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, जबकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित समूहों को उत्पादक परिसम्पत्तियां एवं निवेश उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा पार करने में सक्षम बनाना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में यह उल्लिखित है कि कुल लाभान्वित लाभार्थियों में से कम से कम 40% महिलायें होनी चाहिएं। इसमें यह भी व्यवस्था है कि सहायता प्राप्त परिवारों में से कम से कम 50% अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से होना चाहिए।

ये दोनों ही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

Blocks to be included under Drought Prone Area Programme in Gujarat

1458. SHRI GOPALSINGH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Gujarat has identified twenty Blocks in Mandvi, Mundra, Rapar Talukas of Kachh District of Gujarat where conditions and just similar to those in Drought Prone Areas;

(b) whether for inclusion of those in Drought Prone Areas Programme, this matter has been sent to the National Committee constituted for D.P.P. and D.P.A.P;

(c) whether the Central Government have also constituted a technical committee to consider this matter;

(d) whether the Central Government propose to take a decision in this matter at the earliest; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) In Gujarat Rapar Block of Kutch District is already covered under the Drought Prone Areas Programme (DPAP). In addition to the existing coverage of DPAP in Kutch District, Gujarat has identified Mandvi and Mundra Blocks for inclusion under the Programme.

(b) and (c) This matter was submitted for consideration to the Technical Committee on Daought Prone Area Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) constituted by the Central Government.

(d) and (e) The Technical Committee in its report submitted in April, 1994 recommended inclusion of Mandvi and Mundra Blocks under DDP and transfer of all the seven state Blocks including Rapar to DDP. The recommendations of the Committee have been accepted by the Central Government and communicated to the State Government on 23-11-1994.

Drought Prone Area Programmes in Gujarat

1459. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of districts and blocks covered/to be covered under the Drought Prone Area Programme (DPAP), particularly in Gujarat;

(b) whether Mundra and Mandvi Talukas of Kachh district are not covered so far under this programme;

(c) if so, the reasons therefor;